राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की फिर मिली धमकी

इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का ई-मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर धमकी मिली है। बीते चार दिन में यह दूसरा मौका है, जब हाईकोर्ट में बम धमाका करने की धमकी दी गई है। इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए इस मेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की बात कही गई है। ई-मेल की जानकारी मिलने ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। वहीं न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद कर दी।

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई। वहीं हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला गया। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि बदमाश वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन के कई प्रकार होते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और मैन पावर है। उसका इस्तेमाल करके आरोपियों को जल्दी ही ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही कुछ कामयाबी मिलेगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर मजाक की सी स्थिति बन गई है। बीते डेढ़ माह में हाईकोर्ट को तीन बार बम से उडाने के मेल मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच एजेंसियां अभी तक यह तक मालूम नहीं कर पाई हैं कि ई-मेल कहां से आया है। हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है और कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाता है। जिससे एक और भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होती है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि डढ़ माह में ही तीसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उडाने की धमकी मिलना गंभीर है। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इन दोनों ईमेल की जांच करवानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे है।

पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोर्ट परिसर की पूरी तलाशी लेने के बाद क्लीन चिट दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे बाद से केसों की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुबह बम की धमकी मिलने के चलते अदालतों में सुनवाई नहीं हुई और हजारों प्रकरण प्रभावित हुए।

राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं।

- बम की धमकी के बाद सोमवार को पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया, न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद की, जो कि 2 बजे बाद पुनः शुरू हुई

मुख्यमंत्री ने सुनीं राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में लोगों की समस्याएं

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सचिवालय में दौरा करते हुए अचानक राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन सेंटर 181 पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दो कॉलर्स नवलगढ़ (झुन्झुनूं) के सुधीर और कोटपूतली-बहरोड़ के नेमीचंद से बात कर उकी समस्याओं का भी तुरंत समाधान करवाया।

- 181 पर आ रही समस्याओं की बढ़ाई जाए मॉनिटरिंग : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया और परिवादियों की समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब राजस्थान संपर्क 181 पर समस्याएं सुन रहे थे तो एक कॉल पर नवलगढ़ (झुन्झुनू) के सुधीर ने बताया कि उनके घर के पास साव की ढाणी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। परंतु सड़क के बीच में एक पोल आ रहा है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उस पोल को हटाने के लिए निवेदन किया। जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित कलक्टर ने पोल हटवाया।

इसी प्रकार एक अन्य शिकायतकर्ता नेमीचंद निवासी गोकलपुर गांव, वार्ड नंबर 29 (कोटपूतली-बहरोड़) ने मुख्यमंत्री को फोन पर बताया कि गोकलपुर गांव में वार्ड नंबर 29 में नाले की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी निकलकर सड़क पर भरा हुआ है। जिससे आवागमन में लोगों को समस्या आ रही है तथा बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने इस नाले की जल्द से जल्द सफाई कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आदेश पर संबंधित कलक्टर ने नाले की तुरंत सफाई करवाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 181 हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर आ रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटैण्ड किया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्र खोलेगी भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करेगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कॅरियर परामर्श जैसी सुविधाएं मिल सके। यह पहल राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के समर्पित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विकास, शिक्षा और युवा सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

ज्ञात रहे कि अटल ज्ञान केन्द्रों में ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी पुस्तकें, कॅरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सुविधा होगी। पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1274 केंद्रों को चिन्हित कर इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

- प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली 1274 पंचायतें चिन्हित
- इन जगहों पर ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कॅरियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम होंगे

पिछले दो वर्षों में भजनलाल सरकार ने युवा प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना इसी दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो ग्रामीण युवाओं को शहरों के समकक्ष अवसर प्रदान करेगा। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। अटल ज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की स्वीकृति प्रदान की गई है। करीब 232 करोड़ रुपए से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

'नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण हितैषी'

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है।

आधुनिक और भारतीय शिक्षा के समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा शिक्षा बोर्ड : डॉ. एन.पी. सिंह

प्रयागराज। एएमए कन्वेंशन सेंटर प्रयागराज में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा पद्धित को पुनर्जीवित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय स्थापित करना है। आज देश को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों में आत्मगौरव, भारतीयता, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टि दोनों का विकास कर सके। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने प्रयागराज में संगोष्ठी को संबोधित किया।

डॉ. सिंह ने बताया कि बोर्ड के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, गीता, जैन और बौद्ध दर्शन, भारतीय शूरवीरों की कथाएँ, संवैधानिक मूल्य, गुरुकुल परंपरा और आधुनिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी को संतुलित रूप से जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में भारत के लगभग 120 महान नायकों की जीवनगाथाओं को भी शामिल किया है। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल नौकरी योग्य नहीं बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाएगी। बोर्ड का पाठ्यक्रम यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप भी विकसित किया गया है। यह बोर्ड के समकक्ष है, यह कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों को मान्यता देती है। कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता ले सकते हैं।

विशिष्ट अतिथियों में संयुक्त शिक्षा निदेशक राम नारायण विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव मेजर डॉ. हर्ष कुमार उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी भगवान सिंह भी कार्यक्रम में सहभागी रहे। कार्यक्रम का संचालन बृज मोहन ने किया।